भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 926

उत्तर देने की तारीख-02/12/2024

औद्योगिक और क्षेत्रीय संपर्कों के माध्यम से कॉलेजों में नवोन्मेषी पाठ्यक्रम

†926. श्री सुब्बारायण के.:
श्री सेल्वाराज वी.:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय शिक्षा और नौकरियों के बाज़ार के बीच अनुरूपता नहीं है जिसके परिणामस्वरूप बाज़ार में कुछ नौकरियों के लिए उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) औद्योगिक और क्षेत्रीय संपर्कों के माध्यम से कॉलेजों में नवोन्मेषी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का उद्देश्य देश में शिक्षा की गुणवत्ता में परिवर्तन और सुधार लाना तथा समावेशी, न्यायसंगत और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का एक ऐसा मानक प्रदान करना है जो भविष्य के लिए शिक्षार्थियों को सशक्त बनाए और राष्ट्रीय विकास में योगदान दे। एनईपी 2020 उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) द्वारा स्टार्ट-अप इनक्यूबेशन केंद्रों; प्रौद्योगिकी विकास केंद्रों; अनुसंधान के अग्रणी क्षेत्रों में केंद्रों; अधिक उद्योग-शैक्षणिक संबंधों; और मानविकी और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान सहित अंतर विषय अनुसंधान की स्थापना करके अनुसंधान और नवाचारों को भी बढ़ावा दिया जाता है।

छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने और एनईपी 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने शिक्षा में कौशल शिक्षा का एकीकरण करते हुए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) को अधिसूचित किया है। यह इंटर्नशिप और परियोजनाओं के साथ-

साथ कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम, मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम, क्षमता वृद्धि पाठ्यक्रम जैसे विविध क्षेत्रों के माध्यम से क्रेडिट संचय को भी सक्षम बनाता है। एनसीआरएफ़ में कौशल-आधारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से आवश्यक कुल क्रेडिट का अधिकतम 50% संचय करने का भी प्रावधान है। इन प्रावधानों ने उच्चतर शिक्षण संस्थानों में छात्रों को बहु-विषयक ज्ञान प्रदान करने में सक्षम बनाया है, जिससे वे उद्योग के लिए तैयार हो गए हैं।

इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शिक्षुता अन्तर्निहित डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं ताकि स्नातकों की दक्षता और उसके रोजगार को बढ़ाने के उद्देश्य से अपेक्षित अध्ययन के दौरान व्यावहारिक प्रदर्शन प्रदान उपलब्ध कराया जा सके।

एनईपी 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने और छात्रों को उद्योग प्रासंगिक ज्ञान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने कई कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं:

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग (वीएलएसआई डिजाइन और प्रौद्योगिकी), रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि क्षेत्रों में मॉडल पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम संशोधन समितियों में उद्योग हितधारकों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है।
- छात्रों और संकाय सदस्यों के इंटर्नशिप, कौशल और कौशल संवर्धन की सुविधा के लिए अग्रणी उद्योगों और संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मॉडल इंटर्नशिप दिशानिर्देश जारी किए। इंटर्नशिप विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए एआईसीटीई द्वारा जारी मॉडल पाठ्यचर्या का अनिवार्य घटक है। ये दिशानिर्देश पूर्णकालिक या अंशकालिक इंटर्नशिप प्रदान करते हैं।
- सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच संपर्क की सुविधा के लिए एआईसीटीई द्वारा उद्योग अकादमी गतिशीलता ढांचा शुरू किया गया, जिससे शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग की सुविधा मिली। इसके अतिरिक्त, यह उद्योग-अकादमिक साझेदारी के लिए रूपरेखा प्रदान करता है, जो पारस्परिक रूप से लाभप्रद जुड़ाव को प्रोत्साहित करता है जो दोनों पक्षों को समृद्ध बनाता है।

शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास और प्रतिष्ठित उद्योग भागीदारों के सहयोग से 27 फरवरी 2024 को स्वयम प्लस प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जो उद्योग की अवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों

की पहचान करने और उन्हें शामिल करने तथा शिक्षार्थियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए अपने प्रस्ताव का विस्तार करेगा। यह मंच छात्रों/शिक्षार्थियों को अग्रणी उद्योग और शिक्षा जगत से उच्च गुणवत्ता वाले अधिगम और प्रमाणन कार्यक्रम प्रदान करता है, जो उन्हें पुनः कौशल विकास और कौशल उन्नयन में मदद कर सकता है तथा उन्हें रोजगार के लिए तैयार कर सकता है। शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी मद्रास ने प्रमुख उद्योग भागीदारों के साथ 55 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। 22 नवंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, मंच पर 320 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं और 1.27 लाख से अधिक शिक्षार्थियों ने अपने कौशल वृद्धि के लिए नामांकन किया है।

*****